

उत्तर प्रदेश बड़े पैमाने पर करेगा बजिली बैंकगि

चर्चा में क्यों?

17 फरवरी, 2023 को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर सभी क्षेत्रों में भरपूर नरिबाध बजिली देने के प्रयासों को फलीभूत करने के लिये उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर बजिली बैंकगि करने का फैसला किया है।

प्रमुख बिंदु

- चेयरमैन एम. देवराज ने बताया कि बजिली बैंकगि के तहत सर्दियों तथा सामान्य दनों में जब राज्य में बजिली की मांग औसत अथवा कम रहती है, उस समय कॉरपोरेशन उपलब्ध अतिरिक्त बजिली जम्मू-कश्मीर, तमलिनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक के साथ ही एनटीपीसी को देगा। प्रदेश में बजिली की मांग बढ़ने पर ज़रूरत के मुताबिक इस बजिली को इन राज्यों से वापस लिया जाएगा।
- गौरतलब है कि 2014 में राज्य में महज़ 1 करोड़ 42 लाख 64 हज़ार बजिली उपभोक्ता थे, जो अब बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गए हैं। 2014 में बजिली की अधिकतम मांग, जो 12327 मेगावाट थी, वह 2022 में दोगुने से अधिक 26589 मेगावाट पहुँच गई है। बजिली सप्लाई के घंटों में भारी वृद्धि हुई है। ज़िला मुख्यालय तथा उद्योगों को 24 घंटे बजिली दी जा रही है, गाँवों को भी 6 घंटे अधिक बजिली मुहैया कराई जा रही है।
- उद्योगों को 24 घंटे बजिली मलिन से नविशक भी उत्तर प्रदेश आने को आतुर नज़र आ रहे हैं। वैश्विक नविशक सम्मेलन में आए भारी-भरकम नविशक प्रस्तावों के धरातल पर उतरने पर राज्य की अर्थव्यवस्था में भारी उछाल आएगा। उद्योगों के आउटपुट से राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ने के साथ ही प्रतिव्यक्ति आय में तेज इजाफा होगा।
- माना जा रहा है कि दो से तीन साल के अंदर ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर पहुँच जाएगी। हालाँकि उद्योगों के आने के साथ ही पावर कॉरपोरेशन को आने वाले सालों में बजिली की मांग की संभावित वृद्धि का आकलन नए सरि से करना होगा, जिसकी तैयारी कॉरपोरेशन ने शुरू कर दी है।
- कॉरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज के मुताबिक बजिली बैंकगि के बड़े फैसले के बाद पावर कॉरपोरेशन सर्दियों व आम दनों में राज्य के पास उपलब्ध अतिरिक्त बजिली को पावर एक्सचेंज से बेचेगा नहीं, बल्कि जिन राज्यों से करार हो रहा है, उन्हें दे देगा।
- उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर से 29 मिलियन यूनिट, तमलिनाडु से 61.56 मिलियन यूनिट का समझौता पहली बार किया है। कर्नाटक और एनटीपीसी से करार प्रस्तावित है। बैंकगि के माध्यम से उत्तर प्रदेश से जुड़े राजस्थान ने पछिले वर्ष 449.6 मिलियन यूनिट का करार किया था। अब करीब चार गुना अधिक 1967.8 मिलियन यूनिट की बैंकगि का करार किया है। मध्य प्रदेश से भी बैंकगि का करार हुआ है।
- चेयरमैन का दावा है कि इस प्रयास से प्रदेश में बजिली की कोई दकिकत नहीं होगी। सर्दियों में जब मांग कम रहती है, उस समय उत्पादन गृहों को पूरी क्षमता से चलाया जा सकेगा, क्योंकि दूसरे राज्यों को अतिरिक्त बजिली चली जाएगी। बजिली बैंकगि के तहत कॉरपोरेशन इन राज्यों को सरप्लस बजिली होने पर करार के मुताबिक तय बजिली देगा। ये राज्य जब उत्तर प्रदेश को ज़रूरत होगी तो ली गई बजिली वापस करेंगे।
- इसका लाभ यह होगा कि जब राज्य में जून से सितंबर के बीच बजिली की मांग अधिकतम होती है उस समय भी बजिली की कोई कलिलत नहीं होगी। पावर एक्सचेंज से 12 रुपए और अधिक की दर से बजिली नहीं खरीदी पड़ेगी। हमेशा गर्मी के दनों में पावर एक्सचेंज में बजिली का रेट बहुत अधिक रहता है।
- चेयरमैन ने बताया कि 7413 मेगावाट क्षमता की नई उत्पादन इकाइयों से बजिली का उत्पादन 2025-26 तक शुरू हो जाएगा। 2023-24 के अंत तक इसमें से 5000 मेगावाट की इकाइयाँ चलने लगेंगी।
- 2021-22 में 927 करोड़ रुपए तथा 2022-23 में अब तक 91 करोड़ रुपए की बजिली खरीदी जा चुकी है। 2030 तक राज्य में बजिली की अनुबंधित उत्पादन क्षमता 40392 मेगावाट तक की जानी है। 2023 में अनुबंधित उत्पादन क्षमता 32356 मेगावाट तक ले जाने की है।
- 2022-23 में बजिली की अधिकतम मांग 26589 मेगावाट तक पहुँची जबकि 2014 में अधिकतम मांग 12327 मेगावाट ही थी। 2023-24 में अधिकतम मांग 27776 मेगावाट तक पहुँचने की संभावना है।